

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-2
संख्या- 1507/XXXI(2)/2015-90 (विविध)/2011
देहरादून : दिनांक 15 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के समीक्षा अधिकारी संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2549/XXXI(2)/2011-90(विविध)/2011, दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 द्वारा निर्गत की गयी थी। इस कार्यालय ज्ञाप के निराकरण विषयक प्रस्तर संख्या-34 में उ0प्र0 सचिवालय में चयन वर्ष 1991 के प्रतीक्षासूची से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि इनकी ज्येष्ठता मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या-14296-97/2008 (CC 7870-7871) "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

2- श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल की नियुक्ति रिट याचिका संख्या-32389/1997 एवं विशेष अपील संख्या-256/1998 (नवीन 99/1999) "उत्तर प्रदेश राज्य बनाम योगेन्द्र कुमार पाल व अन्य" के अधीन की गयी थी। उक्त याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2007 एवं इस सम्बंध में प्रतिपक्षीगण द्वारा योजित रिकाल प्रार्थना-पत्र संख्या-265023/2007 में पारित आदेश दिनांक 2.5.2008 के विरुद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14296-97/2008 "योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य" तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-14791-92/2008 "लाल बहादुर सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य" में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2014 पारित किया गया है जोकि निम्नवत है :-

An additional affidavit dated 27th August, 2013, has been filed on behalf of the State of U.P. - Respondent No.1.

Paragraph 7 and 8 of the afore-stated affidavit is being extracted hereunder:

7. That upon deliberation of the facts, especially in deference to the oral observations of this Hon'ble Court and further keeping in view the humanitarian aspects attached and the dependents of the persons who have continued in service on the basis of the order of the High Court, a view was taken in the said meeting that they may be considered to be allowed to remain in service but keeping in view of the implications with respect to different batches of the employees having joined on different dates in their regular appointments, the seniority of these petitioners including the others who are similarly placed (total 39), shall have to be considered after 16.03.2005, the date on which last 2001 batch of direct recruitment has taken place.

✓ SNM क-

8. That the said view to place them in seniority from 16.03.2005 have been taken in view of the fact that three batches of recruitment (i.e. 1995 batch, 1999 batch and 2001 batch) have joined and the last joining took place on 16.03.2005. These 28 petitioners herein (Claimants) and other 11 who are not party to these proceedings, shall have to be placed before the said last appointee in view of the fact that it will become very difficult to reschedule and manage the seniority list. Even if the said efforts would be made, then that will create multiple causes of action for innumerable litigation by different parties claiming to be affected by the said rescheduling of the existing seniority list."

It was acknowledged by the learned counsel representing the State of Uttar Pradesh, during the course of hearing that the position expressed in paragraphs 7 and 8 relates to such of the appellants who have been appointed against vacancies which were filled up in the first instance, but thereafter, became available again.

Learned counsel for the appellants states that he has no objection to the disposal of the instant appeals, in respect of the remaining appellants, in terms of the offer made by the State of U.P., as has been recorded in paragraphs 7 and 8 of the additional affidavit.

In view of the above, the instant appeals, with the consent of the parties, are disposed of in the aforesaid terms.

उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1100/बीस-ई-5-2014-76/2009 दिनांक 07.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैच 1991 के प्रतीक्षा सूची से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को दिनांक 16.03.2005 तक नियुक्त कार्मिकों के पश्चात ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में इस रिट याचिका के अधीन नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल का स्थान उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के समीक्षा अधिकारी संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 के क्रमांक-59 से विलोपित करते हुए उन्हें उत्तराखण्ड सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग की कार्यालय ज्ञाप संख्या-2167/XXX(1)/2005-55(5)/2005, दिनांक 21 जनवरी, 2006 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 172 "ए" पर अनन्तिम रूप से निर्धारित करते हुए कार्यालय ज्ञाप-692/XXX(2)/2015 दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए प्रभावितों से 15 दिन के भीतर आपत्ति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। कार्यालय ज्ञाप के क्रम में श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल द्वारा आपत्ति की गयी है। जिसका निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

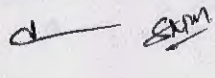

- 1) श्री पयाल द्वारा यह कथन किया गया है कि मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं०-1) श्री पयाल की नियुक्ति पत्र में उनकी नियुक्ति रिट याचिका सं०-32389/97 "श्री योगेन्द्र कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य" एवं विशेष अपील

4 5/11/15

14791-92/2008 श्री योगेन्द्र कुमार पाल बनाम राज्य व अन्य में न तो उत्तराखण्ड राज्य एवं न ही श्री पयाल पक्षकार थे, जिस कारण उक्त निर्णय उन पर लागू नहीं होता है।

संख्या-99/1999 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम योगेन्द्र कुमार पाल व अन्य के अधीन की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.10.2007 को पारित अन्तिम आदेश में मा0 न्यायालय की रिट याचिका सं0-32389/97 में पारित आदेश दिनांक 09.04.1998 को Set aside करते हुए रिट याचिका सं0-32389/97 को खारिज कर दी गयी है। तत्पश्चात् श्री योगेन्द्र कुमार पाल द्वारा योजित रिकॉल प्रार्थना पत्र में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2008 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुए श्री पाल के रिकॉल प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 30.10.2007 एवं 02.05.2008 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-14296-97/2008 श्री योगेन्द्र कुमार पाल बनाम राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2014 के आदेश द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित किया गया। अतः यह कहना कि उक्त आदेश श्री पयाल पर लागू नहीं है, तर्कहीन है। अतः आपत्ति अग्राह्य है।

- 2) श्री पयाल का यह कथन है कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग- उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं 02 के कार्यालय ज्ञाप सं0-692/ दिया गया तथा दिनांक 02.05. XXXI(2)/2015, दिनांक 12 मई, 2015 2008 को अन्तिम निर्णय लिये जाने द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता निर्गत कर प्रकरण से आज तक की तिथि तक मा0 में आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी, जिस उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रम में श्री पयाल द्वारा आपत्तियाँ भी हस्तगत नहीं कराया गया है एवं प्रस्तुत की गयी। जिसका निस्तारण इस मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद आदेश द्वारा किया जा रहा है। अतः यह का क्षेत्राधिकार केवल उत्तर प्रदेश कहना कि इन्हें सुनवाई का कोई अवसर राज्य तक सीमित होने के कारण प्रदान नहीं किया गया, उचित नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य एवं यहाँ के कार्मिक पर लागू किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य के संज्ञान में यह प्रकरण था तो समय से उत्तराखण्ड राज्य एवं उन्हें मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पक्षकार होना चाहिए था। अतः

उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करना संविधान के अनुच्छेद-226 का भी उल्लंघन है एवं जब उक्त आदेश लागू नहीं होता है तो इसके विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 03.02.2014 उन पर लागू करना संविधान का उल्लंघन है।

- 3) उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2014 को, जो निर्णय पारित किया गया था, वह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 27.08.2013 को मा० न्यायालय में योजित अतिरिक्त प्रतिशपथ पत्र के आधार पर पारित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित उक्त प्रतिशपथ पत्र दोनो पक्षों की उभय सहमति के आधार पर दाखिल किया गया, इसमें उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः उक्त समझौता जोकि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्मिक एवं उनकी सरकार के मध्य निष्पादित हुए हैं, को मुझ पर स्वतः लागू करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

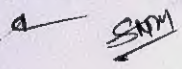
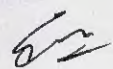
- 4) श्री पयाल द्वारा यह भी अवगत कराया जा रहा है कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2014 के प्रस्तर-08 में उल्लिखित 28 वादी एवं 11 जोकि वादी नहीं थे, का ही उल्लेख है। उक्त 39 कार्मिकों (मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय) में श्री पयाल का नाम सम्मिलित नहीं है। अतः उन पर मा० उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2014 लागू नहीं है।

- 5) श्री पयाल द्वारा यह भी कहा गया है कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-02 के पत्र दिनांक 19.04.2012 द्वारा कार्मिकों

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27.08.2013 को मा० उच्चतम न्यायालय में योजित प्रतिशपथ-पत्र में "इन कार्मिकों को इनकी मा० उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त सेवा में काफी लम्बी अवधि, इन कार्मिकों के आश्रितों आदि पक्षों के दृष्टिगत मानवीय आधार पर इन कार्मिकों को सेवा में बनाये रखने का" अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध श्री पयाल के प्रतिकूल नहीं है। अपितु मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2007, जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति को उचित नहीं माना है, के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक पक्ष मा० उच्चतम न्यायालय में रखा गया। अतः यह कहा जाना कि उ०प्र० के प्रतिशपथ-पत्र के आधार पर लिये गये निर्णय उन पर लागू नहीं होता है तर्कसंगत नहीं है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहबाद के संस्तुति पत्र दिनांक 14.05.1999 में रिट याचिका सं०-32389/97 के अधीन जिन कार्मिकों की संस्तुति उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गयी थी उनमें श्री पयाल का नाम भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 08.08.2014 के प्रस्तर-03 में भी वर्ष 1991 की प्रतीक्षा सूची से नियुक्त एवं वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत कार्मिकों में भी श्री पयाल का नाम सम्मिलित है।

इस सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिका सं०-14296-97/2008 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2014 को अन्तिम निर्णय

को मा० उच्चतम न्यायालय में पारित किया जा चुका है। अतः इस योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं० 14296-14297/2008 के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रश्नगत आपत्ति अग्राह्य है।

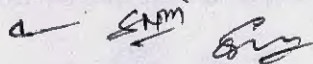
तत्क्रम में उनके द्वारा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में ईम्पलीड करने की अनुमति मांगी गयी किन्तु मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें ईम्पलीड करने की अनुमति नहीं दी गयी एवं न ही विशेष अनुज्ञा याचिका प्राप्त करने की अनुमति दी गयी, इस आधार पर इनका यह कथन है कि उक्त के कारण उन पर मा० उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2014 लागू नहीं होता।

- 6) भारत सरकार के आदेश उ०प्र० पुनर्गठन की धारा-73/74 के अनुसार नियत दिनांक 09.11.2000 से पूर्व की सेवाओं में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः यह उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का उल्लंघन है।

इस सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि इन कार्मिकों की नियुक्ति मा० न्यायालय में लम्बित वाद में होने वाले निर्णय के अधीन की गयी थी। प्रश्नगत निर्णय को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.10.2007 को अपास्त कर दिया है। मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं०-14296-97/2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2014 के अनुपालन में इन कार्मिकों की ज्येष्ठता में संशोधित की जा रही है। अतः प्रश्नगत आपत्ति अग्राह्य है।

- 7) श्री पयाल द्वारा यह भी कहा गया है कि उ०प्र० राज्य व उत्तराखण्ड राज्य दोनों की परिस्थितियों में अन्तर है। उ०प्र० में 2001 बैच द्वारा सीधी भर्ती में नियुक्ति हुयी है, जबकि 2001 बैच का कोई कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में सीधी भर्ती से चयन 2004 बैच द्वारा की गयी है तथा संविलियन नियमावली, 2002 के अन्तर्गत अन्य विभागों के कार्मिक भी सचिवालय में संविलियन कर लिये गये हैं। अतः दिनांक 16.03.2005 के पश्चात इन्हें ज्येष्ठता में

श्री पयाल की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में वर्ष 1999 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-32389/1998 एवं विशेष अपील संख्या-256/1998 (99/1999) के तहत की गयी थी जिसे मा० न्यायालय द्वारा उचित नहीं माना गया। अतः मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2014 में उल्लिखित तिथि से ही ज्येष्ठता दिया जाना बाध्यकारी है।



रखा जाना उचित नहीं है। श्री पयाल द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार उनकी ज्येष्ठता क्रमांक-172'A' निर्धारित करना ज्येष्ठता नियमावली-2002 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.02.2014 का भी उल्लंघन है।

3- श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल को उत्तर प्रदेश सचिवालय की ज्येष्ठता सूची के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में समीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 20.12.2000 को पदोन्नति प्रदान की गयी है तथा समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरान्त समीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 24.10.2011 में ज्येष्ठता क्रमांक-59 पर रखा गया है। अतः श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल का नाम समीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता क्रमांक 59 से एतद्वारा विलोपित करते हुए सहायक समीक्षा अधिकारी की ज्येष्ठता कार्यालय ज्ञाप संख्या-2167/ XXX(1)/2005-55(5)/2005, दिनांक 21 जनवरी, 2006 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-172'A' पर अन्तिम रूप से निर्धारित किया जाता है।

4- कार्यालय ज्ञाप संख्या-2549/XXXI(2)2011 दिनांक 24.10.2011 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2167/ XXX(1)/2005-55(5)/2005, दिनांक 21 जनवरी, 2006 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त कार्यालय ज्ञापों की शेष शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगे।

पी0एस0 जंगपांगी:
सचिव

संख्या- 1507(1) /XXXI(2)/2014-90(विविध) / 2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5) महा निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7) सम्बंधित कार्मिक।
- 8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।